समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

भारत-पाक सीजफायर पर मंडराया खतरा ? अमेरिकी अदालत मे ट्रंप सरकार ने टैरिफ से जोड़ा मामला।

Publisher

Published on 29 May 2025

अमेरिका के व्यापार टैरिफ पर सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन का हैरान करने वाला बयान, भारत-पाकिस्तान की शांति से जोड़ा संबंध।

वॉशिंगटन (29 मई 2025): अमेरिका के पूर्व **राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** की नीतियों को लेकर फिर से एक विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला सीधे **भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम (सीजफायर)** से जुड़ा है। अमेरिका की एक अदालत में ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए उनके **टैरिफ पॉलिसी** की अहम भूमिका रही है।

अमेरिकी कोर्ट मे दिया गया बयान – टैरिफ हटे तो सीजफायर टूट सकता है!
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री **हावर्ड लुटनिक ने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड** में बयान देते हुए कहा कि "राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टैरिफ अधिकारों का उपयोग भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कायम करने के लिए किया था।"

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि ट्रंप के बनाए टैरिफ नियमों को चुनौती दी गई या हटाया गया, तो इससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

टैरिफ नीति को लेकर फिर घिरे ट्रंप
ट्रंप प्रशासन के इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की बहस को नया मोड़ दे दिया है। पहले ही **चीन, यूरोप और भारत** पर लगाए गए टैरिफ को लेकर ट्रंप की खूब आलोचना हो चुकी है, लेकिन अब जब इसे **सीजफायर जैसे संवेदनशील मुद्दे से जोड़ा गया**, तो मामला और भी गंभीर हो गया है।

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा था तनाव

गौरतलब है कि भारत द्वारा **ऑपरेशन सिंदूर** चलाए जाने के बाद, पाकिस्तान की ओर से कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशें हुई थीं। भारतीय सेना के शक्तिशाली **एयर डिफेंस सिस्टम** ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उस दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने डिप्लोमैटिक और व्यापारिक दबाव से दोनों देशों को शांत रहने के लिए मजबूर किया।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.